38 लॉजिस्टिक-वेयरहाउसिंग परियोजनाएं मंजूर

2600 करोड़ का आएगा निवेश, औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए यूपीसीडा की रणनीति

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सेक्टर को प्राथमिकता दे रहा है। यूपीसीडा ने उप्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 और पीआईपी नीति के तहत कुल 38 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इससे करीब 2600 करोड़ का निवेश आएगा।

प्रदेश में प्राप्त लॉजिस्टिक्स परियोजना प्रस्तावों में से छह को यूनिक आईडी जारी करने की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं से विभिन्न जिलों में लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग इकाइयों की स्थापना होगी। इनमें प्रमुख रूप से लखनऊ के सरोजनी नगर में प्राइम शिफ्ट लॉजिस्टिक्स, गाजियाबाद के मोदीनगर में इंटास फार्मास्यूटिकल्स व एसपी लॉजिस्टिक्स, रामपुर के बिलासपुर में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल और ग्रेटर नोएडा में फेयर एक्सपोर्ट्स ने परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं। इन परियोजनाओं में करीब 400 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।

यूपीसीडा से मंजूर 38 परियोजनाएं 523.86 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएंगी जिनमें 2556 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें से 37 परियोजनाएं 483.86 एकड़ भूमि विकसित होंगी और इससे 2486 करोड़ का निवेश होगा। एक परियोजना को पीआईपी नीति के अंतर्गत मंजूरी दी गई है जिसमें 40 एकड़ भूमि पर 70 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।

प्रदेश सरकार की लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य राज्य को लॉजिस्टिक्स हब बनाना है। नीति के तहत राज्य में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउस क्लस्टर, कोल्ड स्टोरेज चेन और वितरण केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूर्ववर्ती लीडा (एक्स-लीडा) अधिसूचित क्षेत्र की महायोजना-2041 में शासन से अनुमोदन के बाद 60 मीटर, 45 मीटर और 30 मीटर चौड़े महायोजना मार्गों का विकास किया जा रहा है। महायोजना-2041 की स्वीकृति के उपरांत अब तक प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 1383 करोड़ का निवेश हो चुका है। प्राधिकरण क्षेत्र में देश की पहली एआई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्नाव में की गई है।

– मयूर महेश्वरी, सीईओ, यूपीसीडा

औद्योगिक विजन को आगे बढ़ा रहे उद्यमी मित्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना सरकार के औद्योगिक विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन्वेस्ट यूपी की ओर से 2023 में शुरू की गई इस योजना के तहत तैनात 120 उद्यमी मित्र निवेशकों और सरकारी तंत्र के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। इनकी तैनाती से न सिर्फ फाइलों की रफ्तार बढ़ी है, बल्कि अटकी परियोजनाएं भी पटरी पर आई हैं। पर, कुछ जिलों में इनकी सुस्ती चुनौती बन रही है।

नोएडा में हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के 879 करोड़ के आरएंडडी सेंटर को समय पर अनुमति दिलवाना उद्यमी मित्रों की भूमिका का बड़ा उदाहरण है। शारदा समूह की 600 करोड़ की हेल्थ सिटी (आगरा), जेके सीमेंट प्रयागराज का 400 करोड़ का प्रोजेक्ट और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की फतेहपुर परियोजना की दिक्कतों को दूर कराने में उद्यमी मित्रों की भूमिका अहम रही। वाराणसी में अमूल की बॉर्डिंग हाउस परियोजना और बाराबंकी की बिनमैक्स एग्रो इंडस्ट्रीज को भी इन्हीं की मदद से मंजूरी मिली। हालांकि, कई जिलों से कुछ उद्यमी मित्रों की ओर से परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समय पर अपडेट न करने और निवेशकों के कॉल या मेल का जवाब देर से देने की शिकायतें सामने आई हैं। कुछ निवेशकों का कहना है कि छोटे और मध्यम स्तर की परियोजनाओं पर बड़े निवेशकों की तुलना में उनपर कम ध्यान दिया जाता है। इन्वेस्ट यूपी ने हाल ही में ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाई है। अब जिलावार परफॉर्मेंस ऑडिट और मासिक समीक्षा बैठकों से कमजोर प्रदर्शन वाले उद्यमी मित्रों की जवाबदेही तय की जा रही है। उन्हें दोबारा प्रशिक्षण देने और फील्ड विजिट अनिवार्य करने की भी तैयारी है। ब्यूरो

टेक्सटाइल पार्कों के आए 700 प्रस्ताव 16 हजार करोड़ निवेश का है अनुमान

निवेश सारथी पोर्टल पर मिल रहे प्रस्ताव, जिलों में 50 एकड़ में बनेंगे पार्क

लखनऊ। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र में निजी निवेशक खासी रुचि दिखा रहे हैं। खासकर जिलों में विकसित होने वाले छोटे टेक्सटाइल (वस्त्र एवं परिधान) पार्कों में। विभाग को संत कबीर के नाम पर 50 एकड़ में विकसित होने वाले इन पार्कों के लिए अब तक 700 से अधिक प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनके जरिये विभिन्न जिलों में करीब 16 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान है।

वाराणसी, मऊ, भदोही, मिर्जापुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोरखपुर और मेरठ जैसे पारंपरिक क्लस्टरों ने यूपी को पहचान दिलाई है। अधिकारियों ने बताया कि निवेश सारथी पोर्टल पर अब तक मिले 700 से ज्यादा प्रस्तावों के लिए 1642 एकड़ भूमि की जरूरत है। इसके जरिये करीब 16 हजार करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। प्रत्येक पार्क में प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना अनिवार्य होगी। बटन, जिपर, लेबल, पैकेजिंग और वेयरहाउस जैसी सहायक इकाइयों के विकास की भी व्यवस्था होगी। निवेश प्रस्तावों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए जमीन की पहचान कर विकसित करने का काम तेज कर दिया है। क्रियान्वयन सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल अथवा नोडल एजेंसी से किया जाएगा।

■ **प्रदेश से साढ़े तीन अरब डॉलर का होता है निर्यात :** वस्त्र एवं परिधान का वैश्विक बाजार वर्ष 2030 तक 23 खरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत इसमें 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ तेजी से बढ़ते देशों की श्रेणी में है। ऐसे में यूपी की भागीदारी अहम है। अभी प्रदेश देश के शीर्ष वस्त्र एवं परिधान निर्यातक राज्यों में शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश से लगभग 3.5 अरब डॉलर का निर्यात हुआ जो देश के कुल वस्त्र एवं परिधान निर्यात का 9.6 प्रतिशत है। इस क्षेत्र का जीडीपी में 1.5 प्रतिशत योगदान है। इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ब्यूरो

स्किल्ड मैनपॉवर, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनी चुनौती

लखनऊ। प्रदेश का टेक्सटाइल क्षेत्र अब प्रदेश के औद्योगिक विकास की नई पहचान बन रहा है। पिछले पांच वर्षों में विभिन्न जिलों में 123 कंपनियों ने करीब 2492 करोड़ के निवेश से उत्पादन शुरू किया है। इससे लगभग 19752 लोगों को रोजगार मिला है। यह उद्योग स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत तो बना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी यूपी में 58 कंपनियों ने 1084 करोड़ के निवेश से 12677 लोगों को रोजगार दिया है। मध्यांचल में 24 इकाइयों ने 812.91 करोड़ का निवेशकर 1912 रोजगार सृजित किए। पूर्वांचल में 39 कंपनियों के 543 करोड़ निवेश से 4563 लोगों को काम मिला है। बुंदेलखंड में भी 5 कंपनियों ने 52 करोड़ का निवेश कर 600 रोजगार सृजित किए हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि स्किल्ड मैनपॉवर की कमी, कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा अब भी बड़ी रुकावटें हैं। ब्यूरो